बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 199 ● नई दिल्ली ● सोमवार 25 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

नशे की लत पूरी करने के लिए सेंधमारी, 10 घंटे में दबोचा नशेड़ी चोर, आठ कांस्य की मूर्तियां बरामद

गुरुग्राम । केशवपुरम थाना पुलिस ने नशे की लत को पूरा करने के लिए सेंधमारी करने वाले युवक को वारदात के दस घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 23 साल के मोहम्मद सैयद के रूप में हुई है। नशे की लत को पूरा करने के लिए उसे पैसे की जरूरत थी और उसने पहली बार सेंधमारी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन, आठ कांस्य मूर्तियों के साथ एक काला बैग बरामद किया है। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि 20 मई को केशवपुरम थाना पुलिस को एक घर में चोरी की शिकायत मिली। शिकायतकर्ता ने बताया कि घर से एक मोबाइल फोन और 55 हजार रुपये की चोरी हुई है।

बाइक सवार तीन लोगों को ट्रेलर ने रौंदा, तीनों की मौत; चालक फरार

राजसमंद। राजसमंद जिले के आमेट थाना क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब परिवार देलाणा भैरूजी के दर्शन के लिए बाइक से जा रहा था। रास्ते में चंद्रभागा नदी की आसन पुलिया पर सामने से तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे आमेट निवासी मुकेश जोशी (40), उनके भांजे लक्ष्यदीप और भतीजे कुलदीप (7) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मुकेश की बहन मधुबाला जोशी (32) और भांजी चारू उर्फ काव्या गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को आमेट अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के बाद अलीगढ़ में खेत में उतारा; दोनों पायलट सुरक्षित

अलीगढ़ । अलीगढ़ के धनीपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले एक प्रशिक्षु जहाज में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट को थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव चंगेरी के पास एक किसान के खेत में जहाज उतारना पड़ा।

इस घटना से ग्रामीणों में भगदड़ मच गई और सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। एडीएम सिटी अतुल गुप्ता ने घटना के संबंध में विवरण दिया है। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह आठ बजकर 25 मिनट पर पायलट ने प्रशिक्षु छात्र के साथ उड़ान भरी थी।

जहाज करीब एक घंटे तक आसमान में उड़ता रहा। इसी दौरान जहाज में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने सुरक्षित स्थान देखकर जहाज को चंगेरी गांव के पास खेत में उतारा। जहाज के पहिए खेत की मिट्टी में धंस गए और वह वहीं रुक गया। जहाज में सवार पायलट और प्रशिक्षु छात्र दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। धनीपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद जहाज में अचानक खराबी आई। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए खेत को सुरक्षित स्थान के रूप में चुना। जहाज के उतरते ही खेत में मौजूद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। बाद में जहाज को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

अधिकारियों का बयान

एडीएम सिटी अतुल गुप्ता ने बताया कि पायलट और प्रशिक्षु छात्र सुरक्षित हैं। उन्होंने सुबह आठ बजकर पच्चीस मिनट पर उड़ान भरी थी। करीब एक घंटे की उड़ान के बाद तकनीकी खराबी आई। पायलट ने सूझबूझ से जहाज को खेत में उतारा। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।

बांग्लादेशी-रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने के लिए बनाए जाएंगे होल्डिंग सेंटर- सीएम शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को रखने के लिए हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्देश दिया है. इन होल्डिंग सेंटर में उन लोगों को रखा जाएगा, जिन्हें बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने के शक में हिरासत में लिया गया है. इन होल्डिंग सेंटर में संदिग्धों को 30 दिन तक हिरासत में रखा जा सकेगा. बंगाल सरकार ने साफ किया है कि इन जगहों का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं किया जाएगा, जिन्हें हाल ही में घुसपैठिया होने के शक में हिरासत में लिया गया है, बल्कि उन लोगों के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें पहले ही पकड़ा जा चुका है जेल में बंद हैं और जिन्हें देश से निर्वासित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है. सचिवालय नबान्न से घुसपैठियों को हिरासत में रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें कहा गया है कि उन लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिन्हें बंगाल में अवैध रूप से रहते हुए पकड़ा गया है, फिर चाहे वे बांग्लादेशी हों या रोहिंग्या. इसमें आगे कहा गया है कि इस मकसद से हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे. इन सेंटर का इस्तेमाल अवैध घुसपैठियों के साथ-साथ राज्य की जेलों से रिहा हुए विदेशी कैदियों को रखने के लिए भी किया जाएगा. केंद्र सरकार ने पहले भी बंगाल में घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें डिपोर्ट करने के निर्देश जारी किए थे. हाल ही में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि पिछली सरकार केंद्र के उन निर्देशों का पालन करने में नाकाम रही थी. सीएम शुभेंदु ने कहा था कि जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है, इस मामले से जुड़े जरूरी कानून लागू कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया था कि जो नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में नहीं आते, उनकी तुरंत पहचान की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. ऐसे लोगों को बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा और फिर डिपोर्ट करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर बोले- इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल वापस मिला

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने रविवार को दावा किया कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल वापस मिल गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, हम वापस आ गए हैं, तुम भूल गए थे कि हम जिंदा रहने के लिए क्या कर सकते हैं। पोस्ट के साथ उन्होंने कॉकरोच की इमेज भी शेयर की। इससे पहले शनिवार को उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी और पर्सनल अकाउंट को हैक किया गया है। वहीं, दीपके ने रविवार को एक्स पर फॉलोअर्स डेटा शेयर कर बताया कि उनके 94% से ज्यादा फॉलोअर्स भारत से हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल किया कि भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों कहा जा रहा है। दरअसल, रिजिजू ने X पर बिना किसी का नाम लिखे पोस्ट कर लिखा था कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गिरोह से फॉलोअर्स जुटाते हैं, जबकि भारत में ही पर्याप्त युवा मौजूद हैं। भारत-विरोधी गिरोह से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है।

वीजा नियमों से भारतीयों पर नस्लभेदी टिप्पणी तक, रूबियो-जयशंकर ने की प्रेस वार्ता

नई दिल्ली । भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनसे अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ बढ़ती नस्लीय टिप्पणियों और ऑनलाइन हेट कैंपेन को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर रुबियो ने कहा कि हर देश में कुछ मूर्ख लोग होते हैं, जो सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर गलत और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें अमेरिका के असली चरित्र को नहीं दर्शातीं। रुबियो ने कहा, अमेरिका एक स्वागत करने वाला देश है। दुनिया भर से लोग यहां आए, अमेरिकी बने और देश की तरक्की में योगदान दिया। भारतीय समुदाय ने भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था और समाज को मजबूत बनाया है।उन्होंने भारतीय समुदाय की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीयों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान दिया है और अमेरिका चाहता है कि यह साझेदारी आगे और बढ़े। वीजा नियमों में हालिया बदलावों को लेकर भी रुबियो ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि J1, F1 और H 1B वीजा से जुड़े बदलाव सिर्फ भारत के लिए नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए लागू किए जा रहे हैं। रुबियो ने कहा कि अमेरिका अपनी इमिग्रेशन प्रणाली को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका को अवैध प्रवास के बड़े संकट का सामना करना पड़ा, इसलिए अब नए नियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह नीति भारत विरोधी नहीं है। रुबियो बोले, हर देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखकर इमिग्रेशन नीति बनाता है। हमारा उद्देश्य एक बेहतर और व्यवस्थित सिस्टम तैयार करना है। इस दौरान अमेरिकी राजदूत Sergio Gor ने भी भारत-अमेरिका रिश्तों को बेहद मजबूत बताया।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार गहरी हो रही है। रुबियो ने भारत-अमेरिका संबंधों को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कई मुद्दों पर मिलकर काम कर सकते हैं। भारत यात्रा के दौरान रुबियो ने प्रधानमंत्री Narendra Modi से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा और QUAD सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

रिपोर्ट कार्ड

मोदी सरकार 3-0 देश में अब अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करने जा रही है, केंद्र सरकार से जुड़े विश्वस्त सूत्र दावा करते हैं कि मोदी सरकार को एक नया चेहरा-मोहरा देने की कवायद शुरू हो चुकी है, मोदी 20 मई को अपनी विदेश यात्रा से वापिस लौटे और अगले ही दिन उन्होंने अपने आवास 'सेवा तीर्थ' पर अपने मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक ली। कहते हैं यह बैठक कोई साढ़े चार घंटे तक चली, जिसमें कैबिनेट सचिव राजीव गाबा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिरी के मार्गदर्शन में तमाम मंत्रियों और उनके मंत्रालयों के कामकाज की एक विस्तृत रिपोर्ट पीपीटी के माध्यम से पीएम के समक्ष प्रस्तुत की गई। सूत्र यह भी बताते हैं कि मंत्रियों के उनके कामकाज के आधार पर बकायदा अंक भी दिए गए थे। जिन मंत्रालयों के कामकाज को सबसे उम्दा आंका गया उन्हें 'ए प्लस' की रैंकिंग दी गई। सूत्रों की मानें तो महज 5 से 6 मंत्रालय ही 'ए प्लस' की रैंकिंग हासिल कर पाने में कामयाब रहे। 'ए प्लस' रैंकिंग में जेपी नड्डा का स्वास्थ्य मंत्रालय, मनोहर लाल खट्टर का पॉवर मंत्रालय, प्रह्लाद जोशी के उपभोक्ता मामले व खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, किशन रेड्डी के कोयला मंत्रालय व नितिन गडकरी के सड़क परिवहन मंत्रालय को रखा गया। जिन मंत्रालयों के कामकाज में आमूल-चूल बदलाव की बात की गई वह है श्रम, शिक्षा, कौशल विकास मंत्रालय आदि। मंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने अनावश्यक खर्चों में कटौती करें, विदेश यात्राओं और विदेशी समिट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं। महीने के 5 दिन देश के अलग-अलग हिस्सों में अपने मंत्रालयों के कार्यक्रम रखें और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश करें। हर मंत्रालय अपनी जवाबदेही के प्रति ज्यादा सजग रहे। जिन क्षेत्रों में मंत्रालय अपने कार्यक्रम लगाने में असमर्थ हो रहा हो वहां पार्टी संगठन से कह कर अपने कार्यक्रम लगवाएं। हर मंत्रालय से एक 'विजन रिपोर्ट' भी तैयार करने को कहा गया है, जिसके आधार पर वह अपने मंत्रालय के लक्ष्य व मानक तय कर सकें। कहा जाता है कि मंत्रियों के साथ अपनी इस बैठक में पीएम ने अपने कुछ सहयोगी मंत्रियों की खुल कर तारीफ की तो, कईयों को कड़वे नसीहतों के घूंट भी पिलाए गए। अब लाख टके का सवाल यह है कि आखिरकार मोदी मंत्रिमंडल का नया चेहरा-मोहरा देखने को कब मिलेगा? तो सूत्र बताते हैं कि इसके लिए अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि 15 जून तक तो अधिमास या मलमास चल रहा है, इस अवधि में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। 18 जून को राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान होने हैं। जुलाई के आखिर में ही संसद के मानसून सत्र की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है तो शायद इस तारीख के आसपास मंत्रिमंडल फेरबदल की कवायद को सिरे चढ़ाया जा सकता है। अगले ही वर्ष मार्च में यूपी-उत्तराखंड समेत पांच राज्यों के तथा नवंबर माह में गुजरात के चुनाव होने वाले हैं। सो, कयास लगाए जा रहे हैं कि सियासी बाजीगर मोदी इन चुनावी राज्यों के सामाजिक समीकरणों को खंगालते हुए अपने मंत्रि परिषद को अंतिम रूप दे सकते हैं। विपक्ष कुछ केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पहले से करता आया है, सो मोदी के लिए भी यह नायाब मौका होगा उनसे पिंड छुड़ाने का। इसके अलावा कई सीनियर मंत्री 2014 की पहली मोदी सरकार से लगातार उनके कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, इनमें से कई 70 वर्ष की आयु भी पार कर चुके हैं, इनमें से भी कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा भाजपा की नजर अब एनडीए में नए गठबंधन साथियों को शामिल करवाने पर टिकी है। अगर शरद पवार मान जाते हैं तो उनकी पुत्री सुप्रिया सूले मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकती हैं, बात तो उद्धव ठाकरे से भी चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से भाजपा लगातार संपर्क में है, अगर हेमंत सोरेन की भाव-भंगिमाएं यही रहीं तो झामुमो भी एनडीए का नया गठबंधन साथी हो सकता है। भाजपा रणनीतिकार डीएमके से भी लगातार संपर्क में हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और पंजाब में आम आदमी पार्टी में एक बड़ी टूट को अंजाम दिया जा सकता है। अगर सब भाजपा की रणनीतियों व उनकी भावनाओं के अनुरूप चला तो फिर इन दलों से आए लोगों को भी दिल्ली में मंत्री बनाने की मजबूरी हो सकती है। सूत्रों की मानें तो स्वयं पीएम चाहते हैं कि 'उनकी पार्टी के जो नेतागण लगातार 10-12 सालों से दिल्ली में सत्ता का सुख भोग रहे हैं अब उन्हें जमीन पर उतारा जाना जरूरी है, यानी इन्हें संगठन की सेवा में लगाया जाए।' सो, मोदी मंत्रिमंडल का आने वाला फेरबदल एक नई शुरूआत का आगाज हो सकता है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इन दिनों कोई थाह नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार वे हैं कहां? भाजपा ने तो बकायदा उनके लिए एक ऑनलाइन 'लुक आउट' नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या सहयोगी दल कांग्रेस इनको भी इस बात का जरा भी इल्म नहीं कि कई मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने और पर्यटन के नाम पर देशभर में घूम-घूम कर जम्मू-कश्मीर का अलख जगाने वाले उमर यूं अचानक आखिर गायब कहां हो गए? उमर के बचाव में उनके 90 वर्षीय पिता फारूक अब्दुल्ला खुल कर सामने आए हैं, पर वे भी फिलहाल उमर के बारे में यह बता पाने में असमर्थ हैं कि आखिरकार इन दिनों उमर हैं कहां? इसी बीच सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी एक अलग मोर्चा खोल दिया है, प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं के आरोप हैं कि उमर गठबंधन की सरकार चलाने में कांग्रेस की उपेक्षा कर रहे हैं, सो इन नेताओं ने दिल्ली से उमर सरकार से अलग होने की बात की है। उमर की असली दिक्कत दरअसल यह है कि इन दिनों वे अपने गठबंधन साथियों से ज्यादा अपने विरोधियों की चिंता कर रहे हैं, वे दिल्ली नीत भाजपा सरकार से जहां मेल-जोल बढ़ाने में जुटे हैं, वहीं राज्य के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से भी अपने संबंधों को बेहतर धार देने में जुटे हैं, जिन उप राज्यपाल पर अक्सर वे राज्य में एक समानांतर सरकार चलाने के आरोप लगाते रहे हैं। गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी और उनकी कंपनी ग्रीन एनर्जी को अमेरिका में अभयदान मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। उन्हें वहां कोर्ट केस से बरी कराने में और उनके ऊपर चल रहे तमाम मामले खारिज करवाने में ट्रंप के आंख-नाक-कान माने जाने वाले वकील रॉबर्ट जिउफ्रा जूनियर की एक महती भूमिका रही है। अदानी पर यह मामला अमेरिका में बाइडन सरकार के जमाने से चल रहा था। जब डोनाल्ड ट्रंप के चहेते व अमेरिका के मशहूर वकील जिउफ्रा ने अदालत में अपने 100 से ज्यादा स्लाइड वाला प्रेजेंटेशन दिया तो इस पर कोर्ट भी एक बार हक्का-बक्का रह गई थी।

तुलसी गाबार्ड का इस्तीफा !

एक तरफ जब अमेरिकी विदेश मन्त्री श्री मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर आये हुए हैं तो दूसरी तरफ उनकी देश की भारतीय मूल की उनकी कैबिनेट सहयोगी राष्ट्रीय गुप्तचर विभाग की निदेशक श्रीमती तुलसी गाबार्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इस्तीफा शुक्रवार को दिया और इसका कारण अपने पति की गंभीर बीमारी बताया मगर पूरी दुनिया जानती है कि ईरान-अमेरिका युद्ध को लेकर उनके राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ गंभीर मतभेद चल रहे थे। वह इस युद्ध के खिलाफ थीं और ट्रम्प सरकार के सामने यह खुलासा कर चुकी थीं कि ईरान के पास किसी प्रकार की परमाणु आयुध सामग्री नहीं है और उसका परमाणु कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। उन्होंने पिछले महीने ही यह खुलासा किया था और बताया था कि ईरान ने पिछले वर्ष तभी परमाणु कार्यक्रम रद्द कर दिया था जब जून 2025 में उसकी अमेरिका व इजराइल के साथ 12 दिन की भीषण लड़ाई हुई थी। जबकि इसके समानान्तर श्री ट्रम्प कह रहे थे कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखे हुए है और अमेरिका का उसके खिलाफ युद्ध का लक्ष्य परमाणु कार्यक्रम रद्द करना है। वास्तविकता यह थी कि विगत 28 फरवरी को जब अमेरिका व इजराइल ने मिलकर ईरान पर युद्ध थोपा था तो ट्रम्प ने कहा था कि उनका लक्ष्य ईरान में पूरी सत्तात्मक व्यवस्था को बदलना है अर्थात वह इस देश का निजाम बदलना चाहते थे। इस सिलसिले में युद्ध शुरू होते ही 29 मई को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या भी अमेरिकी व इजराइली सेनाओं द्वारा कर दी गई मगर ईरान में सत्ता के चरित्र पर कोई असर नहीं पड़ा और आयतुल्ला की जगह ईरानी जनता ने नये नेता का चयन कर लिया और सरकार पूर्व की भांति ही चलती रही। तब श्री ट्रम्प ने कहना शुरू किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरे पश्चिम एशिया के स्थायित्व व शान्ति के लिए खतरा है अतः युद्ध का लक्ष्य इसके परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना है परन्तु जब उन्हीं की सरकार की राष्ट्रीय गुप्तचर विभाग की प्रमुख तुलसी गाबार्ड ने यह घोषणा कर दी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है तो श्री ट्रम्प को बगलें झांकने के लिए मजबूर होना पड़ा था लेकिन इसके बाद से कयास लगाये जा रहे थे कि श्रीमती गाबार्ड अपने पद पर मुश्किल से ही टिकें क्योंकि राष्ट्रपति के साथ उनके मतभेद मुखर हो चुके हैं। श्रीमती गाबार्ड ट्रम्प प्रशासन की चौथी ऐसी कैबिनेट अधिकारी हैं जिन्होंने उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दिया है। उनसे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी विभाग के प्रमुख श्री जो केन्ट ने मार्च महीने में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा देते समय कहा था कि उनकी आत्मा ईरान के विरुद्ध युद्ध करने की गवाही नहीं देती है। इसी मार्च महीने के अन्त में श्री ट्रम्प ने अपनी कैबिनेट के गृह सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टी नोएम का इस्तीफा ले लिया था। नोएम की आव्रजन समस्या के उभरने पर भारी आलोचना हुई थी हालांकि अमेरिकी आव्रजन नीति को बहुत सख्त बनाने का फैसला श्री ट्रम्प का ही था। इसके अलावा अमेरिका में जेफरी एपस्टीन फाइल्स का विवाद उठने के बाद अटार्नी जनरल पाम बोंडी ने भी इस्तीफा दे दिया था। अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा यह मामला ठीक ढंग से न संभाले जाने के विवाद के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया था। वहीं अप्रैल महीने में अमेरिका के श्रम मन्त्री लोरी शावेज-डिरेमर ने भी त्यागपत्र दे दिया था। अतः श्री ट्रम्प के प्रशासन में पिछले दो महीनों के दौरान ही ये इस्तीफे हुए और सभी ईरान से युद्ध शुरू होने के बाद हुए। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पश्चिम एशिया में जो संकट श्री ट्रम्प ने अपनी नीतियों के चलते शुरू किया है उसका असर खुद उनके अपने देश में कितना गहरा है। श्री ट्रम्प के लिए घरेलू मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती आगामी नवम्बर महीने में होने वाले मध्यावधि चुनाव हैं जिन्हें लेकर अमेरिकी राजनीति करवटें ले रही है और वहां की संसद से लेकर सड़कों तक पर इस बारे में चर्चा तेज हो रही है। अपने देश में श्री ट्रम्प की लोकप्रियता में रोजाना गिरावट आ रही है। वह आम जनता में घटकर अब 35 प्रतिशत रह चुकी है जबकि उनको खुद की रिपब्लिकन पार्टी में भी उनके समर्थकों की संख्या में कमी दर्ज हुई है।

श्रीमती गाबार्ड काफी अनुभवी मानी जाती हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की पूर्व कांग्रेस सदस्य भी रही हैं। वह हवाई प्रान्त से कांग्रेस की सदस्य थीं। वह अमेरिका द्वारा विदेशों में युद्ध लड़ने के खिलाफ रही हैं।

मगर जब विगत फरवरी माह के अन्त में अमेरिका ने ईरान से युद्ध लड़ने की घोषणा की तो उनका पक्ष कमजोर हो गया। हालांकि श्रीमती गाबार्ड इस मसले पर चुप रहीं कि क्या उन्हें ईरान द्वारा फारस की खाड़ी में होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग को बन्द किये जाने का अन्दाजा था और क्या उन्होंने इस बारे में ट्रम्प सरकार को आगाह किया था? मगर अमेरिकी सीनेट की गुप्तचर समिति को उन्होंने लिखित रूप से बता दिया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पुनः शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। मगर उन्होंने कभी भी ईरान के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में अपनी भूमिका नहीं बताई और साफ कहा कि यह राष्ट्रपति का अपना फैसला था। इससे लगता है कि अमेरिकी घरेलू राजनीति नवम्बर महीने के आते-आते कोई नया रंग ले सकती है मगर श्री ट्रम्प इस मोर्चे पर काफी सतर्क लगते हैं और उन्होंने ईरान से युद्ध विराम करने के बाद पुनः युद्ध शुरू करने के इजराइल के इरादों में नाइत्तेफाकी दिखानी शुरू कर दी है।

सम्पादकीय...

आओ हल ढूंढें

आज हमारे सामने दिल दहला देने वाली घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चाहे वह मध्य प्रदेश की बेटी के साथ हुई दर्दनाक घटना या नोएडा जैसे शहरों में लड़कियों पर अत्याचार और आत्महत्या के मामले या एक जवान जज बेटे की आत्महत्या का केस। यह केवल अपराध नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक गहरी चेतावनी है। हर दिन कहीं दहेज के कारण बहू प्रताड़ित हो रही है, कहीं किसी लड़की का मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि वह आत्महत्या जैसा कदम उठा लेती है। कहीं कुछ मामलों में झूठे आरोपों और पारिवारिक तनाव के कारण सास, ससुर और परिवार भी पीड़ा झेलते हैं। आखिर कहां गलती है? इतनी घिनौनी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। हमें जरूरत है अपने परिवारों और समाज में हो रही घटनाओं पर चिंतन और मंथन करने की। मुझे लगता है कि आज परिवारों के साथ बैठकर बात करने की परम्परा कम होती जा रही है। बच्चे अपने दुख, डर और तनाव को साझा नहीं कर पा रहे हैं। मोबाइल भी बहुत बड़ा कारण बन रहा है। यही नहीं शादी के बाद लड़की से हर चीज परफैक्ट करने की उम्मीद की जाती है। कहीं दहेज का दबाव, कहीं नौकरी और घर दोनों को सम्भालने का बोझ, कहीं तुलना। यह सब मानसिक दबाव पैदा करते हैं, कई लड़कियां ससुराल से भी सपनों की दुनिया की उम्मीद रखती हैं। जब जिन्दगी की वास्तविकता का सामना करती हैं तो सहन नहीं कर पातीं। यही नहीं आज युवा में क्रोध, अहंकार बढ़ रहा है। सहनशक्ति भी कम हो रही है। छोटी-छोटी बातों पर रिश्ते टूट रहे हैं। लोग समझौता और धैर्य भूलते जा रहे हैं। ''मैं ही सही हूं'' की भावना परिवारों को तोड़ रहा है। डिप्रेशन, अकेलापन, तनाव यह शब्द बहुत सुनने को आ रहे हैं और हो भी रहे हैं। कुछ लोग अपराध करने से भी नहीं डरते। समाज में नैतिक शिक्षा, मानवता, संस्कारों की कमी आ रही है। यही नहीं फेसबुक पर दिखावा यानी शो ऑफ भी एक जानलेवा कारण बन रहा है। सोशल मीडिया की दिखावटी जिन्दगी भी कारण बन रही है। माता-पिता की शिक्षा में भी कमियां आ रही हैं। आज जरूरत है बेटियों को केवल सहन करना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना चाहिए। लड़कियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है। शादी को केवल सामाजिक प्रतिष्ठा न बनाएं, बल्कि अच्छे संस्कार और समझ को महत्व दें। यही नहीं बहू को बेटी जैसा सम्मान दें। आने वाली लड़की (बहू) को समय और अपनापन दें। दहेज जैसी बुराई को पूरी तरह खत्म करें। लड़कियों के अन्दर एक विश्वास, एक समझ डालनी जरूरी है। हर परिस्थिति में आत्महत्या समाधान नहीं है। जीवन बहुत अनमोल है। यदि कोई समस्या है तो परिवार, मित्र, कानून या समाज से सहायता लें। अपने गुस्से या गलत सलाह में आकर पूरे परिवार को झूठे मामलों में फंसाना भी उचित नहीं है।

'कॉकरोच' जनता पार्टी

भारत के संविधान में जब यह निर्दिष्ट है कि किन्हीं भी दो समुदायों को आपस में भिड़ाने व लड़ाने की कार्रवाई भी राष्ट्र के खिलाफ ही देखी जायेगी तो पूरी युवा पीढ़ी को निजाम बदलने की ताकीद करने वाली कार्रवाई को भी इसी नजर से देखना होगा। इसी वजह से भारत के गुप्तचर विभाग ने सरकार को आगाह किया है कि काकरोच पार्टी की गतिविधियों से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है जिसकी वजह से एक्स मंच पर दिपके का खाता भारत में प्रतिबन्धित कर दिया गया। सरकार ने यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 की धारा 69(ए) के तहत की। मगर दिपके ने अपना खाता कल ही दूसरे डिजिटल में इंस्टाग्राम पर खोल लिया जिस पर लाखों समर्थक एक ही दिन में आ गये जबकि भारत का युवक ऐसी गतिविधियों से अनभिज्ञ ही बना हुआ है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों की जांच हो क्योंकि डिजिटल मंचों पर समर्थक बढ़ाने के लिए वित्तीय फीस भी दी जाती है। इन सब बातों से ऊपर हमें भारत में बहुत सजग रहने की जरूरत है कि कहीं विदेशी षड्यन्त्रकर्ता कोई विनाशकारी ख्वाब तो संजोये नहीं बैठे हैं। बेशक कुछ राजनीतिक दलों को प्रधानमन्त्री श्री मोदी की कार्यप्रणाली से शिकायत हो सकती है मगर ये दल केवल संवैधानिक रास्ते से ही तो अपना विरोध प्रकट करते हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत न तो श्रीलंका है और न नेपाल या ट्यूनीशिया अथवा बांग्लादेश। हमने हर संकट पर केवल संवैधानिक रास्तों से ही पार पाया है।

मेरा यह निश्चित मत है कि भारत हमेशा से गांधी व बुद्ध का देश था, है और रहेगा। जहां तक राजनीतिक उठा-पटक व राष्ट्रीय संवेदनाओं का सम्बन्ध है तो इनका संकट खड़ा होने पर हमें केवल और केवल गांधी की शरण में ही जाना पड़ेगा। इस सन्दर्भ में हाल ही में विदेश में बैठे एक युवक 'अभिजीत दिपके' ने डिजिटल मीडिया मंच 'एक्स' पर जिस 'कॉकरोच जनता पार्टी' का गठन किया और उसके समर्थन में लाखों युवक इस मंच पर आ गये, उससे यही पता चलता है कि भारत की संवैधानिक राजनीतिक प्रणाली को चुनौती देने का षड्यन्त्र रचा जा रहा है क्योंकि भारतीय युवा वर्ग कभी भी अराजकता का समर्थक नहीं रहा है। अतः यह पता लगाया जाना बहुत जरूरी है कि दिपके के समर्थक कौन लोग हैं और इन्हें वित्तीय मदद कहां से मिल रही है। इसके साथ ही मैं देश के मोदी विरोधी वैकल्पिक मीडिया कर्मियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि वे सरकार विरोध में अन्धे होकर कॉकरोच जनता पार्टी के एजेंडे को बढ़ावा न दें क्योंकि ऐसा करके वे केवल भारत में संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था का विरोध ही करेंगे। हम दिपके जैसे युवकों को भटके हुए युवक भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत सोच-समझकर रणनीतिक तरीके से देश की युवा पीढ़ी को तात्कालिक आवेश में लाकर भारत से कानून का राज खत्म करना चाहते हैं। कानून का राज भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की 'आत्मा' है जिसके समाप्त होने पर अराजकता की शुरूआत होती है। बेशक भारत में फिलहाल बेरोजगार वृद्धि दर औसत से बहुत ज्यादा है और बदलती भू-राजनीति की वजह से विश्व के विकसित देशों में कुशल भारतीय युवकों के रोजगार पाने के साधनों में कमी हो रही है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि विदेशों में बैठे चन्द लोग भारत की पूरी युवा पीढ़ी को सड़कों पर उतर कर पूरे निजाम को ही बदलने की भूमिका बांधने लगें। हमने जिस लोकतन्त्र को अपनाया है और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता आन्दोलन लड़ने वाली पूरी पीढ़ी जिस व्यवस्था को हमें सौंप कर गई है उसमें कुछ खामियों का उभर आना भारत की बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के तहत आश्चर्य नहीं है परन्तु इसे पूरी तरह उलट देने का सपना पालना केवल राष्ट्रद्रोह ही कहलायेगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो अपना पांच सूत्री कार्यक्रम जारी किया है उसके अनुसार यदि किसी मतदाता का वोट काटना गलत पाया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को गैरकानूनी कार्रवाई अधिनियम (यूएपीए) के तहत सजा दी जानी चाहिए और उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आजकल मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुद्दा गर्म है और दिपके के साथी लोगों ने आम जनता की इस प्रक्रिया के विरुद्ध उपजी भावनाओं को भुनाने की गरज से ही इसे गंभीर आपराधिक श्रेणी में डाला है, जिससे युवा वर्ग का जोशीला खून खौलने लगे और वह संविधान की प्रक्रिया के विरुद्ध ही सड़कों पर उतर आये।

यह माना जा सकता है कि भारत के विभिन्न प्रान्तों की सरकारों में से कुछ ने न्याय देने के मामले में जनता की तात्कालिक भावनाओं को अपने पक्ष में भुनाने की गलती की हो मगर इसका मतलब यह नहीं निकलता कि हम पूरी संवैधानिक व्यवस्था के ही परखचे उड़ाने की तरकीबें बांधने लगें। राज्य सरकारों की ऐसी कथित लोकप्रिय न्यायिक कार्यवाइयों के खिलाफ न्यायालय में जाने के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और कई मामलों में न्यायालयों ने राज्य सरकारों को फैसलों का बदला भी है और कड़ी फटकार भी लगाई है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में बदले या प्रतिशोध के लिए सरकारों के काम करने पर प्रतिबन्ध इसीलिए है क्योंकि हर मामले को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस बारे में हमें गांधी जी का यह कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि 'लोकतन्त्र में न्याय पाने व अधिकार मिलने में देरी तो हो सकती है मगर संघर्ष के बाद जो भी मिलता है वह कानूनी रूप से स्थायी होता है'। देश की नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि जिस तमिलनाडु राज्य में हाल ही में फिल्म अभिनेता विजय की चुनावों के बाद सरकार गठित हुई है, उसी में पचास के दशक तक स्व. रामस्वामी नायकर 'पेरियार' की 'द्रविड़ कषगम' पार्टी बहुत लोकप्रिय थी मगर यह पृथक 'द्रविड़नाडु' की मांग करती थी। उस समय मद्रास प्रान्त कहे जाने वाले इस राज्य में पेरियार अपनी राजनीतिक व सामाजिक विचारधारा की वजह से बहुत लोकप्रिय भी थे। मगर पृथक द्रविड़नाडु की उनकी मांग से अधिसंख्य तमिल जनता असहमत थी। भारतीय संविधान के अनुसार जो पार्टी राष्ट्रीय अखंडता को स्वीकार न करती हो, वह चुनाव नहीं लड़ सकती थी। 1956 में भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू इस सन्दर्भ में एक संविधान संशोधन भी लाये थे। अतः तमिलनाडु के पेरियार के चेले कहे जाने वाले नेता स्व. सी.एन. अन्नादुरै ने तब द्रविड़ कषगम से अलग होकर 1956 में अपनी 'द्रविड़ मुनेत्र कषगम' पार्टी बनायी थी और 1962 के आम चुनावों में हिस्सा लिया था। अतः बहुत स्पष्ट है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल केवल तभी राजनीतिक प्रक्रिया में दाखिल हो सकता है जब वह संविधान को मानने की शपथ ले। इसलिए कॉकरोच पार्टी खुलेआम नक्सलियों की तरह संविधान को हाशिये पर डाल कर यदि जनभावनाएं भड़काने का काम करती है तो यह सरासर राष्ट्रद्रोह है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भारी खतरा हो सकता है।

भारत के संविधान में जब यह निर्दिष्ट है कि किन्हीं भी दो समुदायों को आपस में भिड़ाने व लड़ाने की कार्रवाई भी राष्ट्र के खिलाफ ही देखी जायेगी तो पूरी युवा पीढ़ी को निजाम बदलने की ताकीद करने वाली कार्रवाई को भी इसी नजर से देखना होगा। इसी वजह से भारत के गुप्तचर विभाग ने सरकार को आगाह किया है कि काकरोच पार्टी की गतिविधियों से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है जिसकी वजह से एक्स मंच पर दिपके का खाता भारत में प्रतिबन्धित कर दिया गया। सरकार ने यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 की धारा 69(ए) के तहत की। मगर दिपके ने अपना खाता कल ही दूसरे डिजिटल में इंस्टाग्राम पर खोल लिया जिस पर लाखों समर्थक एक ही दिन में आ गये जबकि भारत का युवक ऐसी गतिविधियों से अनभिज्ञ ही बना हुआ है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों की जांच हो क्योंकि डिजिटल मंचों पर समर्थक बढ़ाने के लिए वित्तीय फीस भी दी जाती है। इन सब बातों से ऊपर हमें भारत में बहुत सजग रहने की जरूरत है कि कहीं विदेशी षड्यन्त्रकर्ता कोई विनाशकारी ख्वाब तो संजोये नहीं बैठे हैं। बेशक कुछ राजनीतिक दलों को प्रधानमन्त्री श्री मोदी की कार्यप्रणाली से शिकायत हो सकती है मगर ये दल केवल संवैधानिक रास्ते से ही तो अपना विरोध प्रकट करते हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत न तो श्रीलंका है और न नेपाल या ट्यूनीशिया अथवा बांग्लादेश। हमने हर संकट पर केवल संवैधानिक रास्तों से ही पार पाया है। जहां तक व्यवस्था में विकृतियों का प्रश्न है तो इनका निदान भी हमारा संविधान ही पुख्ता तरीके से करने में सर्वथा सक्षम है।

मायावती पर कांग्रेस का दांव!

सरकारें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों या टिप्पणियों को अक्सर ही अनदेखा करती ही रहती हैं, लेकिन अब तो निचली अदालतें भी ऐसा करने लगी हैं। पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने जमानत के बारे में बड़ी टिप्पणी की। दोनों जजों ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। उन्होंने यह भी कहा कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए के मामले में भी यही नियम लागू होता है। यह टिप्पणी करते हुए दोनों जजों ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत खारिज होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जमानत खारिज करते हुए दो जजों की बेंच ने जमानत को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के फैसले की अनदेखी की। उनके कहने का अर्थ यह था कि उमर को भी जमानत मिलनी चाहिए। दो जजों की बेंच की टिप्पणियों से लगा कि पांच साल से ज्यादा समय से जेल में बंद उमर को अब जमानत मिल जाएगी। उमर को शुक्रवार को हाई कोर्ट से तीन दिन की सशर्त अंतरिम जमानत मिल भी गई लेकिन इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की एक निचली अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी। उमर ने अपने दिवंगत चाचा के चेहल्लुम (चालीसवें) में शामिल होने के साथ-साथ अपनी मां सर्जरी के समय मौजूद रहने के लिए 15 दिन की जमानत मांगी थी, लेकिन निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

भाजपा नेताओं को पीछे छोड़ रहे हैं सेना प्रमुख

पाकिस्तान को लेकर इतिहास और भूगोल की बात करते हुए भाजपा और संघ के नेता हमेशा कहते रहे हैं कि क्या करें खराब पड़ोसी मिल गया है। इसके आगे वे कहते हैं कि इतिहास बदला जा सकता है लेकिन भूगोल नहीं। हालांकि यह गलत है। असल में इसका उलटा होता है। इतिहास नहीं बदला जा सकता है। बड़े नेता भूगोल बदलते हैं। इंदिरा गांधी ने भूगोल बदला था। बिस्मार्क से लेकर हेलमुट कोल और माओ से लेकर व्लादिमीर पुतिन तक सबने भूगोल बदला है। लेकिन भाजपा के नेता भूगोल की बजाय इतिहास बदलने की बात करते हैं। अब इससे आगे बढ़ कर इतिहास और भूगोल की बात सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ले आए हैं। जनरल द्विवेदी दो महीने बाद जुलाई में रिटायर होने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा है कि पाकिस्तान सोच ले कि उसे इतिहास में दफन होना है या भूगोल में रहना है। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा तो भारत उसको भूगोल से मिटा देगा। आधुनिक युग में किसी देश के कुछ इलाके को अपने देश में मिला कर उसका भूगोल बदलने की मिसाल तो है लेकिन पूरा देश ही मिट जाए या पूरे देश को कोई देश अपने में मिला ले ऐसा नहीं हुआ है। भारत भी पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता है और करने का इरादा भी नहीं है। फिर भी रिटायर हो रहे जनरल साहब की बात दिन-रात पाकिस्तान को मिटाने की बात करने वालों के एक समूह को भी अच्छी लगी होगी। अब देखना होगा कि जुलाई के बाद क्या होता है?

केरल और तमिलनाडु में राजनीतिक सद्भाव की मिसाल

देश के कर्कशता भरे मौजूदा राजनीतिक माहौल में तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों ने एक अच्छी मिसाल बनाई है। जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें पश्चिम बंगाल और असम में तो पक्ष और विपक्ष के बीच दुश्मन जैसे रिश्ते हैं। चुनाव के बाद भाजपा नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए तो विपक्ष के नेताओं ने भी पहले दिन से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष का कोई भी नेता न तो शुभेंदु अधिकारी और न ही हिमंत बिस्व सरमा के शपथ ग्रहण में गया। तमिलनाडु में भी विपक्ष का कोई नेता मुख्यमंत्री विजय की शपथ में भी नहीं गया। लेकिन शपथ के बाद विजय लगभग सभी विपक्षी नेताओं से मिले। उन्होंने एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन से मुलाकात की तो वाइको से भी मिले। विजय ने विपक्ष के प्रति सद्भाव की ऐसी मिसाल बनाई, जो पहले देखने को नहीं मिलती थी। एक समय तमिलनाडु की राजनीति ऐसी थी कि करुणानिधि ने जयललिता को जेल भेजा था तो जयललिता की पुलिस करुणानिधि और मुरासोली मारन को घसीटते हुए जेल ले गई थी। लेकिन विजय ने उसे बदला है। उधर केरल में भी मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने ऐसी ही मिसाल बनाई। वे कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री मनोनीत होने के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता पिनराई विजयन से मिलने उनके घर गए। दोनों की हंसते मुस्कुराते फोटो और वीडियो जारी हुए। यह लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीर थी, जो दिखाती है कि राजनीति दल आपस में प्रतिद्वंद्वी होते हैं, दुश्मन नहीं। ये तस्वीर यह भी दिखाती है कि चुनाव हारने से जीवन समाप्त नहीं होता है।

तेल बचाने के लिए नेताओं की नौटंकियां

राजनीतिक रूप से भारत एक प्रदर्शन प्रधान देश है। यहां नेता जिस तरह अपनी नौटंकी का प्रदर्शन करते हुए जनता को मूर्ख बनाते हैं, वैसा दुनिया के किसी और देश के नेता नहीं करते होंगे। अभी तेल का वैश्विक संकट शुरू हुआ तो दुनिया भर के देशों ने अपने यहां इस संकट से निपटने के उपाय शुरू किए। लेकिन भारत में सरकार ने पहले तो 70 दिन तक संकट को स्वीकार ही नहीं किया गया क्योंकि पांच राज्यों में चुनाव होने थे। चुनावों में बेहिसाब रैलियां हुईं, रोड शो हुए, नेताओं के विशेष विमान उड़ते रहे। शपथ ग्रहण समारोह तक यह तमाशा चला। उसके बाद अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल, डीजल, गैस आदि किफायत से खर्च करने को कहा। मिसाल बनाने के लिए एक दिन वे भी दो गाड़ियों के काफिले से निकले। उसके बाद उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने जो तमाशा शुरू किया, वह लोगों के लिए सिरदर्द बन गया और सोशल मीडिया को मजाक का मसाला मिल गया। भाजपा के नेताओं में होड़ मची है कि कौन कितने क्रिएटिव तरीके से दिखावा कर सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा मीडिया को दिखाने के लिए एक दिन मेट्रो से चले। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में खबर आई कि उन्होंने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने सबको पीछे छोड़ते हुए एक दिन बाइक चलाते हुए सचिवालय गए। राजस्थान में एक जज साहेब ने साइकिल से अदालत जाने का फैसला किया तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सबको पीछे छोड़ते हुए पैदल चल कर सचिवालय गए। अब देखना है कि इससे आगे की क्रिएटिविटी कौन दिखाता है!

मायावती पर कांग्रेस का दांव

सोशल मीडिया में इस बात का मजाक बनाया जा रहा है कि कांग्रेस के दो नेता राजेंद्रपाल गौतम और तनुज पुनिया अचानक मायावती से मिलने पहुंचे थे लेकिन मायावती के कार्यालय के बाहर से गार्ड ने उन्हें लौटा दिया। पहली नजर में यह मामला मजाक का ही दिखता है। याद करें कि कैसे पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ अन्य नेताओं को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के घर के बाहर पहुंच गए थे और कह रहे थे कि उनकी पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाए। राजद ने ऐसा नहीं किया। इसके बावजूद ओवैसी की पार्टी के पांच उम्मीदवार मुस्लिम बहुल सीटों से चुनाव जीत गए। ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्रपाल गौतम ने बसपा प्रमुख पर दांव खेला है। वे तनुज पुनिया के साथ मायावती से मिलने गए। उन्हें पता था कि मायावती नहीं मिलेंगी। फिर भी वे गए तो इसका मकसद चुनाव से पहले राज्य के दलित मतदाताओं को यह संदेश देना था कि कांग्रेस

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/06862)

जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार

नई दिल्ली । इस साल के संसद रत्न पुरस्कारों के लिए 12 सांसदों और चार संसदीय समितियों का चयन किया गया है. निजी संगठन 'प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन' ने एक बयान में बताया कि बीजेपी के जगदंबिका पाल (उत्तर प्रदेश), पीपी चौधरी (राजस्थान), निशिकांत दुबे (झारखंड) और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे (महाराष्ट्र) पुरस्कारों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में चुने गए सांसदों में शामिल हैं.

प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रवीण पटेल (उत्तर प्रदेश), विद्युत बरन महतो (झारखंड), लुम्बाराम चौधरी (राजस्थान), हेमंत विष्णु सवरा (महाराष्ट्र), स्मिता उदय वाघ (महाराष्ट्र), नरेश गणपत म्हस्के (महाराष्ट्र), मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र) और नरहरि अमीन (गुजरात) को इस साल बजट सत्र के अंत तक संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा.

चार संसदीय समितियां भी शामिल

इसके अलावा इस सम्मान के लिए चार संसदीय समितियों को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण पुरस्कार के लिए चुना गया है. इनमें चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली कृषि समिति, भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली वित्त समिति, सप्तगिरि शंकर उलाका की अध्यक्षता वाली ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समिति और अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली कोयला एवं खान समिति शामिल हैं. इस साल चुने गए चेहरों में देश के कई बड़े और अनुभवी राजनेता शामिल हैं, जिन्होंने लंबे समय तक शासन व्यवस्था को करीब से देखा है. बता दें कि इस गौरवशाली लिस्ट में शामिल जगदंबिका पाल और चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं. इनके अलावा गुजरात से आने वाले नरहरि अमीन पूर्व उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत साल 2010 में हुई थी और यह पुरस्कार उन सांसदों को दिए जाते हैं जो पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने के लिए संसद में खासे एक्टिव रहते हैं. इसका मकसद सांसदों को प्रोत्साहित करना और जनता के बीच संसदीय कार्यवाही को लोकप्रिय बनाना है. ये पुरस्कार संसद में सक्रियता, बहस में भागीदारी, प्रश्न पूछने और विधायी कामकाज में योगदान के आधार पर प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है.

43 डिग्री सेल्सियस में झुलस रहा दिल्ली और एनसीआर, हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

नई दिल्ली । उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है. हीट वेव भी लगातार जारी है. सूर्य देव के तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं. भीषण गर्मी से लोग का जीना मुहाल हो गया है. दिल्ली एनसीआर सहित नोएडा ग्रेटर नोएडा का तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. मौसम विभाग का साफ़ तौर पर यह कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम बना रहेगा. फिलहाल इस भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही. इस भीषण गर्मी से लोगों को काफी दिक्कत होगा सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली एनसीआर सहित नोएडा ग्रेटर नोएडा में भीषण गर्मी का कर देखने को मिल रहा है. इस भीषण गर्मी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पूरा दिल्ली एनसीआर तंदूर की भट्ठी की तरह उबलने लगा है, और लगातार हीट वेव पड़ने लगी है. भीषण गर्मी का तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है जो लोगों के लिए बेहद खराब माना जा रहा है. जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है. लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर देखने को मिल रहा है. वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम और रुला सकता है, हीट वेव और बढ़ सकती हैं. तापमान का ग्राफ भी और बढ़ सकता है. इसलिए लोगों से या अपील है कि वह

अपने घर से अधिक जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले वरना घर से बाहर न निकले. जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं. अपने चेहरे को कपड़े से ढ्क कर और सनग्लासेस लगाकर व छाता लेकर चले, अपने साथ पानी की बोतल लेकर चलें ताकि आप लोग बढ़ते भीषण गर्मी और हीट वेव से बच सके. फिलहाल अभी इस भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही. आने वाले दिनों में गर्मी और रुला सकती है. सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही चल रहे हैं और जहां वाहनों की लंबी कतारें लगी होती थीं, वो अब खाली हैं. लेकिन भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर कम लोग ही दिखाई दे रहे हैं. तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से लोग फिलहाल बचते हुए दिखाई दे रहे हैं.

सड़कों पर धूल-धुएं को रोकेंगे एयर प्यूरीफायर- सीएम ने अल्ट्रा-मॉडर्न प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों का किया निरीक्षण

नई दिल्ली । सड़कों पर देसी तकनीक के इस्तेमाल से हवा में फैले धुएं, धूल और जहरीले कणों को खत्म किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में लगाए गए तीन आधुनिक एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम का ग्राउंड निरीक्षण किया और कहा कि अब प्रदूषण के खिलाफ सरकार सालभर मिशन मोड में काम करेगी। निरीक्षण के दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने रामा रोड स्थित सत गुरु राम सिंह मार्ग पर लगाए गए एसटीआर-101 फिल्टर रहित एयर प्यूरीफायर सिस्टम का निरीक्षण किया। सड़क के बीचों-बीच बिजली के खंभों पर इसकी 21 डिवाइस लगाई गई हैं। यह सिस्टम हवा में मौजूद पीएम 1, पीएम 2.5, पीएम 10, धूल, धुआं और कार्बन कणों को कम करने के लिए तैयार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इसकी हाई-फ्रीक्वेंसी चिप तकनीक बैक्टीरिया और वायरस को भी निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह प्रणाली प्रति घंटे करीब तीन लाख लीटर हवा को प्रोसेस कर सकती है। इसमें किसी पारंपरिक फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। यह पूरी तरह ऑटो-क्लीनिंग और कम रखरखाव वाली तकनीक है, जिसमें आईओटी आधारित लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदूषण के खिलाफ अभियान केवल सर्दियों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार पूरे साल तकनीक, रिसर्च और इनोवेशन से समाधान पर काम करेगी। मेक इन इंडिया के तहत विकसित स्वदेशी तकनीकें पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही हैं। दिल्ली सरकार ऐसी तकनीकों को बड़े स्तर पर अपना रही है। मुख्यमंत्री ने कीर्ति नगर से मायापुरी मार्ग पर लगी देश की पहली ईवी एंटी स्मॉग गन के काम को देखा। यह मोबाइल और जीरो एमिशन सिस्टम जरूरत के हिसाब से अलग-अलग इलाकों में इस्तेमाल हो सकती है। यह हाई प्रेशर पंप और हाई स्पीड फैन की मदद से बेहद महीन जल कणों का छिड़काव करती है, जिससे हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक नीचे बैठ जाते हैं।

अधिकारियों के मुताबिक यह तकनीक क्लीन एयर कॉरिडोर बनाती है, जिससे ट्रैफिक वाले इलाकों में दृश्यता और वायु गुणवत्ता दोनों बेहतर होंगी। निरीक्षण करते हुए तीसरा पड़ाव कीर्ति नगर फायर स्टेशन के पास लगाया गया पवन-3 रोडसाइड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस रहा।

48 घंटे में1 करोड़ की हाई-प्रोफाइल चोरी का खुलासा, एक दबोचा; सोना-चांदी, हीरे के गहने और नकदी बरामद

नई दिल्ली । दक्षिण दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटों के भीतर ग्रेटर कैलाश में हुई 1 करोड़ रुपये की हाई-प्रोफाइल चोरी के मामले को सुलझा लिया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी किए गए सोने, हीरे और चांदी के आभूषणों के साथ-साथ ?3.57 लाख नकद भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 20 मई को ग्रेटर कैलाश पुलिस थाने में पम्पोश एन्क्लेव में हुई एक बड़ी चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि दिन के समय घर बंद था और रात में लौटने पर ताले टूटे हुए पाए गए और लगभग 1 करोड़ के सोने, हीरे और चांदी के आभूषणों के साथ-साथ 6.5 लाख नकद भी चोरी हो गए थे। इसके तुरंत बाद ग्रेटर कैलाश पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस मामले की जांच के लिए दो विशेष टीमें गठित की गईं।दोनों टीमों ने तकनीकी निगरानी स्थानीय खुफिया जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के गहन विश्लेषण का इस्तेमाल करते हुए एक सघन जांच शुरू की। 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और आरोपी की लगभग 10 किलोमीटर तक की आवाजाही को ट्रैक किया गया। खुफिया सूचना के आधार पर 22 मई को एक छापा मारा गया और आरोपी सांवरा गुर्जर उर्फ सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया। गहन पूछताछ के दौरान उसने अपराध करने की बात स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए सोने, हीरे के आभूषणों और नकदी की भारी मात्रा में बरामदगी की गई।

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- प्राइवेट स्कूल अब बिना सरकारी मंजूरी बढ़ा सकेंगे फीस

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि बिना शिक्षा विभाग से मंजूरी लिए फीस बढ़ा सकते हैं कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि डीओई को सौंपे बयानों में स्कूलों की ओर से प्रस्तावित फीस में बढ़ोतरी 2027 के शैक्षणिक सत्र से ही लागू होगी। कहा कि किसी भी स्कूल को पिछले शैक्षणिक सत्रों के लिए फीस या अन्य चार्जेस का कोई भी बकाया मांगने या वसूली नहीं कर पाएगा। बेंच ने यह साफ किया कि जो स्कूल किसी एकेडमिक सेशन की शुरुआत में फीस बढ़ाते हैं। उन्हें सेशन शुरू होने से पहले डीओई को प्रस्तावित फीस का एक स्टेटमेंट जमा करना होगा।

फैसले से रेगुलेटरी सुरक्षा कमज़ोर हो सकती

वहीं इस आदेश के बाद माता-पिता ने चिंता जताई और कहा कि इस फैसले से रेगुलेटरी सुरक्षा कमज़ोर हो सकती है। उनका मानना है कि वे विरोध करने और नियमों को चुनौती देने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। इस ऑर्डर को बहुत बड़ा झटका बताते हुए, 115 द्वारका के एक स्टूडेंट ने कहा, हम (पेरेंट्स) चिंतित हैं कि पहले से मौजूद स्कूलों को अब सिर्फ़ उनके प्रस्तावित स्ट्रक्चर को मानने से फ़ीस बढ़ाने की लगभग पूरी पावर मिल जाएगी। उन्होंने कहा, अगर ऐसे सुरक्षा उपाय कमज़ोर किए गए तो आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रावधान भी खतरे में आ सकते हैं। यह क्लॉज़ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसी एजेंसियों द्वारा प्राइवेट स्कूलों को रियायती दरों पर इंस्टीट्यूशनल ज़मीन देते समय लगाई गई अलॉटमेंट शर्तों से निकला है। इन शर्तों ने बड़े स्कूलों को बिना किसी छूट के ट्यूशन फ़ीस बढ़ाने से रोक दिया है। यह आदेश कैपिटल में प्राइस स्कूल द्वारा सभी कानूनी पसंदों को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद की पृष्ठभूमि में है, जिसके कारण माता-पिता बार-बार विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। इस विवाद ने सरकार को दिल्ली स्कूल बिजनेस (पारदर्शिता और शिक्षा का विनियमन अधिनियम, 2025) लाने के लिए भी प्रेरित किया, जिसमें स्कूल-स्तरीय विनियमन समितियों, अभिभावक समितियों और जिला-स्तरीय पैनल द्वारा फीस में कमी लाने का प्रावधान है। हालांकि, 2026-27 के अकादमिक सत्र के लिए कमेटी-बेस्ड सिस्टम के रोलआउट को इस साल चुनौती दी गई है, या दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पिछले साल की तरह ही फीस लेने की अनुमति वाले स्कूलों के साथ नए कानून के तहत मंजूरी दी गई है। कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि इस फैसले ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है, जबकि कई परिवार पहले से ही फीस के विवादों से जूझ रहे हैं।

दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ने कहा, इस फैसले से पेरेंट्स के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, जब तक कि कोर्ट फीस प्रपोज़ल की जांच करने, स्कूल अकाउंट्स का ऑडिट करने और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक तय और समय-सीमा वाला सिस्टम नहीं बनाता। जब कोर्ट खुद ही आदेश दे रहा है, तो किससे पेरेंट्स की उम्मीद टूट जाती है। उन्होंने कहा, कोर्ट सही व्यवस्था करने में नाकाम रहा है। फैसला डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता।

स्कूलों ने पहले तय सीमा से ज़्यादा चार्ज किया

कोर्ट ने कहा कि छ्रश्व मुनाफ़ाखोरी और कमर्शियलाइज़ेशन को रोकने के लिए फ़ीस को रेगुलेट कर सकता है, लेकिन प्राइवेट बिना मदद वाले स्कूलों के फ़ाइनेंस को माइक्रो-मैनेज नहीं कर सकता। अभिभावक इस बात पर चिंता जताते हैं कि क्या डॉल के लिए प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर का प्रॉफिटियरिंग या फंड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए काफी होगा। मैटी ने आरोप लगाया कि स्कूलों ने पहले तय सीमा से ज़्यादा चार्ज किया है।

कानूनी चुनौती और विरोध पर विचार कर रहे पेरेंट्स

अभिवाकों का कहना है कि अगर यह ऑर्डर लागू रहता है, तो स्कूल कुछ सालों में 51,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक बदल सकते हैं, मैनरी ने कहा, और कहा कि माता-पिता कानूनी चुनौती और विरोध पर विचार कर रहे हैं। महेश मिशेस, जो द्वारका के एक सोशल वर्कर हैं और चाइल्डलॉस्टडीज़ करते हैं, ने कहा कि इटिस्ट पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जो यूके में हैं, वे एक गलत सिस्टम के नतीजों को झेल रहे हैं। प्राइवेट शॉक के ये नतीजे, एक गलत सिस्टम का सीधा नतीजा हैं।

सुरक्षा अधिकारों के लिए सड़क पर उतर सकते हैं अभिभावक

उन्होंने कहा कि सुरक्षा अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं है। इससे पेटिट्स के बीच भरोसा कम हुआ है, हेविड। अगर समस्या की जड़ है गुरुवार को, क्या एक बार फिर उसी सिस्टम पर ज़िम्मेदारी डालना समझदारी होगी जो पहले ही खत्म हो चुका है? अपने आदेश में, जस्टिस अनूप खंभानी ने प्राइवेट स्कूलों के दिए गए प्रस्तावों को खारिज करने वाले छ्रह्र के आदेशों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि एकेडमिक सेशन की शुरुआत में क्षछ्रह्र की मंजूरी न देना कानूनी तौर पर जायज़ था। कोर्ट ने कहा कि वह परडिटरिंग, कमेडलाइज़ेशन या कैपिटेशन फीस को रेगुलेट कर सकता है, लेकिन प्राइवेट गैर-सरकारी स्कूलों के फाइनेंस को माइक्रो-मैनेज नहीं कर सकता।

मुबारकपुर डबास में वाल्मीकि समाज के लिए नई उम्मीद- Tiger Group करेगा मंदिर का पुनर्निर्माण

नई दिल्ली, (ए.के. चौधरी) मुबारकपुर डबास गांव में वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़े वाल्मीकि मंदिर को अब नई पहचान मिलने जा रही है। मंदिर के पुनर्निर्माण और विकास की जिम्मेदारी Tiger Group ने उठाई है। इस पुण्य कार्य की शुरुआत अजय चौधरी उर्फ अंजू भाई ने 50,000 रुपये की सहयोग राशि देकर की। उनके इस कदम के बाद समाज के युवाओं में नया उत्साह देखने को मिला।

Tiger Group के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक परचा के नेतृत्व में समाज के युवा लगातार समाज सेवा के कार्यों में जुटे हैं। मंगलवार को समूह के सभी सदस्य मंदिर स्थल पर पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि समाज को भरोसा दिलाया कि यह मंदिर केवल भवन नहीं, बल्कि समाज के सम्मान, एकता और संस्कृति का प्रतीक बनेगा। स्थानीय लोगों ने Tiger Group के प्रयासों की सराहना की। समाज के लोगों का कहना है कि उन्हें इन युवाओं पर गर्व है जो निस्वार्थ भाव से समाज और धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं।

116 नम्बर रेलवे फाटक के पास खून से लतपथ मिला सफाई कर्मचारी

हाथ व गर्दन की नस कटी मिलने से मचा हड़कंप

गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर

भटनी देवरिया।

नगर पंचायत भटनी में कार्यरत सफाई कर्मचारी राजेश बासफोर निवासी हतवा गाँव रविवार को 116 नम्बर रेलवे फाटक के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोशी की हालत में मिला। उसके हाथ और गर्दन की नस कटी हुई दिखाई देने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रेलवे फाटक के पास खून से लथपथ हालत में पड़े राजेश को देखकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भटनी लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही भटनी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल में जुट गई। पुलिस घटना के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की छानबीन कर रही है। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

ट्रेन में अचेत मिला युवक, जहर खुरानी की आशंका

कप्तानगंज, कुशीनगर।

कप्तानगंज रेलवे जंक्शन पर रविवार सुबह सीवान से आने वाली 55115 पैसेंजर ट्रेन में एक युवक अचेत अवस्था में मिलने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। युवक की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। चिकित्सकों ने प्रथम दृष्ट्या जहर खुरानी की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह लगभग 8:35 बजे सीवान से कप्तानगंज पहुंची 55115 पैसेंजर ट्रेन प्लेटफार्म संख्या-1 पर पहुंची। ट्रेन की नियमित जांच के दौरान आरपीएफ जवानों को एक बोगी में लगभग 38 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा मिला। आरपीएफ ने तत्काल इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर द्वारा रेलवे अस्पताल के फार्मासिस्ट को मौके पर बुलाया गया। प्राथमिक जांच के बाद युवक को बेहतर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वर्तमान में युवक का उपचार आरपीएफ की निगरानी में कराया जा रहा है। युवक की तलाशी के दौरान उसके पास से बलिया से सीवान तक का मेल-एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट बरामद हुआ है। हालांकि उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉ. फैसल अब्बास ने बताया कि युवक अचेत अवस्था में रेलवे पुलिस द्वारा अस्पताल लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्ट्या मामला जहर खुरानी का प्रतीत होता है।

अक्सर जहर खुरान गिरोह ट्रेन यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनकी नकदी और सामान लेकर फरार हो जाते हैं। घटना के बाद रेलवे पुलिस युवक की पहचान करने तथा मामले की जांच में जुट गई है।

पडरौना में सोमवार सुबह चार घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति

पडरौना, कुशीनगर । विद्युत उपकेंद्र पडरौना के अंतर्गत न्यू 5 एमवीए परिवर्तक के स्थापना कार्य के चलते सोमवार 25 मई 2026 को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि विद्युत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य से विद्युत उपकेंद्र पडरौना में नए 5 एमवीए परिवर्तक का स्थापना कार्य कराया जा रहा है। कार्य के दौरान सुरक्षा कारणों से संबंधित क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रखी जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि निर्धारित समय से पूर्व बिजली से संबंधित आवश्यक कार्य पूर्ण कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विद्युत विभाग के अनुसार कार्य पूरा होने के बाद विद्युत आपूर्ति पुनः बहाल कर दी जाएगी।

तमकुही राज ओवरब्रिज के पास सड़क हादसे में महिला गंभीर घायल

तमकुही राज,कुशीनगर । जनपद के तमकुही राज थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर करीब 1 बजे हुए सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान ग्राम सभा बसडिला बुजुर्ग निवासी 28 वर्षीय नीतू देवी पत्नी बाबूलाल गोड के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबूलाल गोड अपनी पत्नी नीतू देवी के साथ मोटरसाइकिल से तमकुही राज की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तमकुही राज ओवरब्रिज के समीप बाइक अनियंत्रित होकर असंतुलित हो गई, जिससे नीतू देवी सड़क पर गिर पड़ीं। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल एंबुलेंस एवं परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल महिला को जिला अस्पताल रविंद्र नगर धूस पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद नीतू देवी को निगरानी में भर्ती कर लिया। डॉक्टरों के अनुसार सिर में गंभीर चोट होने के कारण उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। परिजनों ने बताया कि महिला का उपचार जारी है।

पडरौना विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की संगठनात्मक बैठकें संपन्न

कुशीनगर।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के उद्देश्य से रविवार 24 मई को पडरौना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न शक्ति केंद्रों पर संगठनात्मक बैठकें आयोजित की गईं। बैठकें पिपरा बाजार राम जानकी मंदिर, पिपरा बाजार शक्ति केंद्र, जंगल बकुलहा जूनियर हाई स्कूल जंगल बकुलहा तथा नरचोवा बहोरा रामनगर में संपन्न हुईं। इस दौरान संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण तथा आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंडल अध्यक्ष महेश रौनियार ने कहा कि संगठन की शक्ति ही विजय का आधार होती है। समर्पित कार्यकर्ता और मजबूत रणनीति के माध्यम से ही विकास का संकल्प जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने शक्ति केंद्र प्रभारियों, संयोजकों एवं बूथ अध्यक्षों से शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार बूथ स्तर पर संगठनात्मक कार्यों को पूर्ण करने का आह्वान किया। बैठक में ÷मन की बात÷ कार्यक्रम पर चर्चा एवं टिफिन बैठक की रूपरेखा तैयार करने, बूथवार जातीय समीकरण की सूची बनाने, बूथ प्रभारी एवं बूथ पालक नियुक्त करने, बूथ समिति एवं पन्ना प्रमुख गठन करने तथा बूथवार मठ-मंदिर एवं महंत-पुजारियों की सूची तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। शक्ति केंद्र संयोजकों के साथ संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आगामी कार्ययोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सशक्त संगठन, सक्रिय कार्यकर्ता और जनसेवा का संकल्प ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। बैठक में मंडल अध्यक्ष दिनेश राय, शक्ति केंद्र संयोजक भोला जायसवाल, हरीश पांडेय, शक्ति केंद्र प्रभारी विनय जायसवाल एवं शशिकांत पांडेय, बूथ अध्यक्ष बालक पासवान, हरिंदर कुशवाहा, काशीनाथ गौतम, जयराम त्रिपाठी, द्वारिका मिश्रा, ओमप्रकाश जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

छितौनी के विकास मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी से मिले समाजसेवी

खड्डा, कुशीनगर।

नगर पंचायत छितौनी के विकास से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं जनहित के मुद्दों को लेकर पत्रकार एवं समाजसेवी ओमप्रकाश कुमार भास्कर तथा दिवाकर कुमार ने जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने नगर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। मुलाकात के दौरान बिजली, पेयजल, सड़क व्यवस्था, पनियहवा स्थित नारायणी नदी घाट की सफाई तथा शिव मंदिर के सुंदरीकरण सहित कई विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। समाजसेवी ओमप्रकाश भास्कर ने जनहित से जुड़े इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की मांग उठाई। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्थलों का शीघ्र निरीक्षण कराने तथा आवश्यक कार्यों को नियमानुसार पूरा कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इस मुलाकात के बाद स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि नगर पंचायत छितौनी की प्रमुख समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा तथा विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।